



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1441]

नई दिल्ली, सोमवार, जुलाई 6, 2015/आषाढ़ 15, 1937

No. 1441]

NEW DELHI, MONDAY, JULY 6, 2015 /ASADHA 15, 1937

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 जुलाई, 2015

सं. 59/2015

का.आ.1827(अ).—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खंड (15) के उप-खंड (iv) के मद (ज) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्वारा निम्नलिखित सारणी के कॉलम (2) में उल्लिखित संस्थाओं को वित्त वर्ष 2015-16 के दौरान यहां नीचे विनिर्दिष्ट की गई शर्तों के अधीन उक्त सारणी के कॉलम (3) में उल्लिखित राशियों के बराबर की राशि के कर मुक्त, सुरक्षित, प्रतिदेय, अपरिवर्तनीय बांडों के निर्गम हेतु प्राधिकृत करती है:-

शर्तें

1. पात्रता:- इन बांडों का ग्राहक बनने हेतु निम्नलिखित पात्र होगा:-

- खुदरा व्यष्टि निवेशक (आरआईआई);
- अर्हक संस्थागत क्रेता (क्यूआईवी);
- अपने-अपने संबंधित अधिनियमों के अनुपालन के अधीन निगम (सांविधिक निगमों सहित), न्यास, साझेदारी वाली फर्म, सीमित देनदारी की साझेदारियां, सहकारी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक एवं अन्य कानूनी संस्थाएं; और
- उच्च निवल मूल्य वाले व्यष्टि (एचएनआई)।

2. बांडों की अवधि:- बांड की अवधि दस, पंद्रह या बीस वर्ष होगी।

3. स्थायी खाता संख्या:- ग्राहकों के लिए अपना स्थायी खाता संख्या (पैन) को बांड निर्गमकर्ता को उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।

4. ब्याज की दर:-

- संदर्भ सरकारी प्रतिभूति (जी-सेक) दर पर आधारित कूपन दरों की अधिकतम सीमा होनी चाहिए;

- (ii) संदर्भ सरकारी प्रतिभूति दर नियत आय मुद्रा बाजार तथा भारतीय व्युत्पन्न संघ (एफआईएमएमडीए) द्वारा यथासूचित समकक्ष परिपक्वता अवधि हेतु सरकारी प्रतिभूति की उत्कृष्ट प्रतिभूति आय की औसत होगी जो कि दैनिक आधार (कार्यकारी दिवस) पर होगी ताकि सार्वजनिक निर्गम के मामले में कंपनी रजिस्ट्रार (आरओसी) अथवा कंपनी विनियम तथा संस्थागत बिक्री के मामले में निर्गम शुरू करने की तिथि के साथ अंतिम विवरण पत्र दाखिल करने से तुरंत पहले आने वाले शुक्रवार को समाप्त हो रहे दो सप्ताहों तक बनी रहती है;
- (iii) एएए श्रेणीकृत निर्गमकर्ताओं हेतु खुदरा व्यष्टि निवेशकों (आरआईआई) के मामले में अधिकतम कूपन दर संदर्भ सरकारी प्रतिभूति दर से 55 आधार अंक कम होगी, तथा ऊपर उल्लिखित (i) के (ii),(iii) एवं (iv) में संदर्भित अन्य निवेशक वर्ग के मामले में संदर्भ सरकारी प्रतिभूति दर से 80 आधार अंक कम होगी;
- (iv) निर्गमकर्ता संस्था की श्रेणी एए+ होने के मामले में अधिकतम दर एएए श्रेणीकृत संस्थाओं हेतु अधिकतम दर से 10 आधार अंक ऊपर होगी, [खंड (iii) में दिए गए अनुसार];
- (v) निर्गमकर्ता संस्था की श्रेणी एए अथवा एए- होने के मामले में, अधिकतम दर एएए श्रेणीकृत संस्थाओं हेतु अधिकतम दर से 20 आधार अंक ऊपर होगी, [खंड (iii) में दिए गए अनुसार];
- (vi) अधिकतम दरें व्याज के वार्षिक भुगतान पर लागू होगी तथा व्याज भुगतानों के चुकौती कार्यक्रम के अर्द्ध वार्षिक बदले जाने के मामले में व्याज दरों को 15 आधार अंकों से घटाया जाएगा;
- (vii) खुदरा व्यष्टि निवेशकों पर लागू व्याज की उच्चतर दरें उनके द्वारा बांडों को गैर-खुदरा निवेशकों को हस्तांतरित करने के मामले में उपलब्ध नहीं होगी।

5. निर्गम खर्च एवं दलाली:-

- (i) संस्थागत बिक्री के मामले में निर्गम का कुल खर्च निर्गम के आकार के 0.25 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए तथा सार्वजनिक निर्गम के मामले में इसे निर्गम के आकार के 0.65 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए;
- (ii) निर्गम खर्च में निर्गम से जुड़े सभी खर्च जैसे दलाली, विज्ञापन, मुद्रण, पंजीकरण आदि शामिल होते हैं।

6. सार्वजनिक निर्गम:-

- (i) प्रत्येक संस्था द्वारा निर्गम किए बांडों की कुल राशि का कम से कम 70 प्रतिशत सार्वजनिक निर्गम के माध्यम द्वारा उद्भूत होना चाहिए।
- (ii) ऐसे सार्वजनिक निर्गम के 40 प्रतिशत को खुदरा व्यष्टि निवेशकों हेतु सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

7. संस्थागत बिक्री:-

- (i) बांडों की संस्थागत बिक्री का रास्ता अपनाते समय प्रत्येक संस्था द्वारा भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (ऋण प्रतिभूतियों का निर्गम एवं सूचीकरण) विनियमन 2008 के विनियम II अनुसार प्रत्येक संस्था द्वारा बही-निर्माण प्रक्रिया को अपनाया जाना चाहिए जिसमें बोलियां संस्था द्वारा विनिर्दिष्ट अधिकतम सीमा के अधीन कूपन दर पर लगायी जाएगी तथा आबंटन मूल्य बोली पर किया जाएगा।
- (ii) बांडों का भुगतान एक निश्चित कूपन के साथ प्रीमियम के लिए तथा उसी के लिए किया जाएगा ताकि दस्तावेज को एकल अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभूति पहचान संख्या (आईएसआईएन) के अंतर्गत कारोबार किया जा सके तथा लाभ उद्भूत की गई कीमत के आधार पर परखा जाएगा तथा इसके पश्चात आबंटन उच्च कीमत (न्यूनतम लाभ) के लिए किया जाएगा;
- (iii) व्याज की उच्चतम सीमा दर उपर्युक्त पैरा (4) में निर्दिष्ट दर की तुलना में या तो बराबर अथवा कम होगी;
- (iv) बोली लगाने के समय निर्गम हेतु बोली लगा सकने वाले व्यवस्थापकों की संख्या की कोई सीमा नहीं होगी।

8. बांडों की धन वापसी

- (i) बांडों को जारीकर्ता संस्था धन वापसी के देय हो जाने के उपरांत उधार ली गई निधि की वापसी के लिए अपनी योग्यता को प्रदर्शित करने हेतु एक वित्तीय योजना वित्त मंत्रालय को प्रस्तुत करेगी;
- (ii) उप पैरा (i) में संदर्भित वित्तीय योजना संबंधित संस्था के निदेशक मंडल के संकल्प द्वारा विधिवत अनुसमर्थित निर्गम के बंद होने के तीन माह के भीतर वित्तीय अनुभाग अवसंरचना प्रभाग, आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय को प्रस्तुत की जाएगी।

9. मर्चेट बैंकरो का चयन:-

- i. मर्चेट बैंकरो का चयन पारदर्शी पूर्व अर्हता मानदंडों के साथ प्रतिस्पर्धा बोली प्रक्रिया द्वारा किया जाएगा तथा अंतिम चयन वित्तीय बोलियों के मूल्यांकन पर आधारित होगा।
- ii. आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के अंतर्गत लाभ तभी ग्राह्य होगा यदि ऐसे बंध पत्रों का धारक अपना नाम तथा धृति संस्था के साथ पंजीकृत कराता है।

- iii. कंपनी अधिनियम, 2013 तथा भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (ऋण प्रतिभूतियों का निर्गम तथा सूचीयन) विनियम, 2008 में विनिर्दिष्ट लोक निर्गम अपेक्षाओं के अनुपालन में किया जाएगा जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ कंपनी रजिस्ट्रार के पास एक विवरण-पत्रिका को दाखिल करना शामिल है, जैसा लागू हो।

सारणी

क्र.सं.	कंपनियां	बांडों की आबंटित राशि (करोड़ रूपए में)
(1)	(2)	(3)
1	भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण	24000
2	भारतीय रेल वित्त निगम (आईआरएफसी)	6000
3	आवास तथा शहरी विकास निगम लिमिटेड (हूडको)	5000
4	इंडियन रेन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड (आईआरईडीए)	2000
5	विद्युत वित्त निगम लिमिटेड (पीएफसी)	1000
6	ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड (आरईसी)	1000
7	एनटीपीसी लिमिटेड	1000

स्पष्टीकरण: इस अधिसूचना के प्रयोजनार्थ,-

- अर्हक संस्थागत विक्रेताओं (क्यू आई बी) से वही तात्पर्य होगा जैसा कि भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (प्रकटीकरण तथा निदेशक संरक्षण) दिशानिर्देश 2000 द्वारा उन्हें परिभाषित किया गया है।
- खुदरा एकल निवेशक से तात्पर्य उस एकल निवेशक से है जो अविभाजित हिंदू परिवार (कर्ता द्वारा) तथा अनिवासी भारतीय, वापसी पर तथा गैर-वापसी आधार पर प्रत्येक निर्गम में 10 लाख रुपये तक का आवेदन करता हो तथा एकल निवेशक जो 10 लाख रुपये से अधिक का निवेश करता हो उसे उच्च नेटवर्थ एकल निवेशक के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा।
- अनिवासी भारतीय को जारी बांड समय-समय यथा संशोधित विदेश विनियम प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 6 तथा धारा 47 की उपधारा (3) के खंड (ख) के अंतर्गत क्रमशः जारी अधिसूचना सं. फेमा 4/2000-आरबी, दिनांक 3 मई, 2000 तथा अधिसूचना सं. फेमा 20/2000-आरबी दिनांक 3 मई, 2000 के उपबंधों के अधीन होंगे।
- इस अधिसूचना के पैरा (4) में संदर्भित क्रेडिट रेटिंग का तात्पर्य उस क्रेडिट रेटिंग से है जैसा कि क्रेडिट रेटिंग एजेंसी द्वारा परिभाषित किया गया है जिसे भारतीय प्रतिभूति तथा विनियम बोर्ड एवं भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुमोदित किया गया है तथा जिन मामलों में किसी संस्था को एक से अधिक रेटिंग एजेंसी द्वारा अलग-अलग रेटिंग प्रदान की गई हो तो उनमें से निचली रेटिंग पर विचार किया जाएगा।

[फा.सं. 178/27/2015-आ.क.नि.-1]

दीपशिखा शर्मा, निदेशक

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th July, 2015

No. 59/ 2015

S.O.1827(E).—In exercise of the powers conferred by item (h) of sub-clause (iv) of clause (15) of section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby authorises the entities mentioned in column (2) of the Table given below, to issue, tax-free, secured, redeemable, non-convertible bonds during the financial year 2015-16, aggregating to amounts mentioned in column (3) of the said table, subject to the conditions, namely :-

CONDITIONS

- Eligibility** - The following shall be eligible to subscribe to the bonds:-
 - Retail Individual Investors (RIIs);
 - Qualified Institutional Buyers (QIBs);
 - Corporates (including statutory corporations), trusts, partnership firms, Limited Liability Partnerships, Co-operative banks, regional rural banks and other legal entities, subject to compliance with their respective Acts; and
 - High Networth Individuals (HNIs).
- Tenure of bonds** - The tenure of the bonds shall be for ten or fifteen or twenty years.

- 3. Permanent Account Number** - It shall be mandatory for the subscribers to furnish their Permanent Account Number to the issuer of the bonds.
- 4. Rate of interest** -
- (i) There shall be a ceiling on the coupon rates based on the reference Government security (G-sec) rate;
 - (ii) the reference G-sec rate shall be the average of the base yield of G-sec for equivalent maturity reported by Fixed Income Money Market and Derivative Association of India (FIMMDA) on a daily basis (working day) prevailing for two weeks ending on the Friday immediately preceding the filing of the final prospectus with the Exchange or Registrar of Companies (ROC) in case of public issue and the Issue opening date in case of private placement;
 - (iii) the ceiling coupon rate for AAA rated issuers shall be the reference G-sec rate less fifty five basis points in case of RIIs and reference G-sec rate less eighty basis points in case of other investor segments referred to at (ii), (iii) & (iv) of paragraph 1 above;
 - (iv) in case the rating of the issuer entity is AA+, the ceiling rate shall be ten basis points above the ceiling rate for AAA rated entities [as given in clause(iii)];
 - (v) in case the rating of the issuer entity is AA or AA-, the ceiling rate shall be twenty basis points above the ceiling rate for AAA rated entities [as given in clause(iii)];
 - (vi) these ceiling rates shall apply for annual payment of interest and in case the schedule of interest payments is altered to semi-annual, the interest rates shall be reduced by fifteen basis points;
 - (vii) the higher rate of interest, applicable to RIIs, shall not be available in case the bonds are transferred by RIIs to non retail investors.
- 5. Issue expense and brokerage** -
- (i) In the case of private placement, the total issue expense shall not exceed 0.25 per cent of the issue size and in case of public issue it shall not exceed 0.65 per cent of the issue size;
 - (ii) the issue expense would include all expenses relating to the issue like brokerage, advertisement, printing, registration etc.
- 6. Public issue** -
- (i) At least seventy per cent of the aggregate amount of bonds issued by each entity shall be raised through public issue;
 - (ii) forty per cent of such public issue shall be earmarked for RIIs.
- 7. Private placement** -
- (i) While adopting the private placement route to issue the bonds, each entity shall adopt the book building approach as per regulation 11 of the Securities and Exchange Board of India (Issue and Listing of Debt Securities) Regulations, 2008, wherein bids shall be sought on the coupon rate subject to a ceiling specified by the entity and the allotment shall be made at the price bid;
 - (ii) the bonds shall be paid for and issued at a premium with a fixed coupon, to facilitate trading of the instrument under a single International Securities Identification Number (ISIN) and the yield shall be computed based on the price quoted and allotment shall be done for best price (lowest yield) thereof;
 - (iii) the ceiling rate of the interest shall either be equal to or lower than the rate mentioned in paragraph 4 above;
 - (iv) while calling for bids, there shall be no limit on the number of arrangers who can bid for the issue.
- 8. Repayment of bonds** -
- (i) The issuer entity shall submit a financing plan to the Ministry of Finance to demonstrate its ability to repay the borrowed funds on the repayment becoming due;
 - (ii) the financing plan referred in sub-paragraph (i) shall be submitted to the Infra-Finance Section, Infrastructure Division, Department of Economic Affairs, Ministry of Finance, within three months of closure of the issue, duly supported by a resolution of the respective entity's Board of Directors.
- 9. Selection of merchant bankers** -
- (i) Merchant bankers shall be selected through competitive bidding process with transparent pre-qualification criteria and the final selection shall be based on financial bids;
 - (ii) the benefit under section 10 of the Income-tax Act, 1961(43 of 1961) shall be admissible only if the holder of such bonds registers his/ her or its name and the holding with the entity.
 - (iii) the issue of bonds shall be made in compliance with the public issue requirements specified in the Companies Act, 2013 and Securities and Exchange Board of India (Issue and Listing of Debt

Securities), Regulations, 2008, including inter-alia the filing of a prospectus with the Registrar of Companies, as applicable.

TABLE

Sl. No.	Entities	Allocated amount of bonds (` in crore)
(1)	(2)	(3)
1	National Highways Authority of India (NHAI)	24000
2	Indian Railways Finance Corporation (IRFC)	6000
3	Housing and Urban Development Corporation (HUDCO)	5000
4	Indian Renewable Energy Development Agency (IREDA)	2000
5	Power Finance Corporation Limited (PFC)	1000
6	Rural Electrification Corporation Limited (REC)	1000
7	NTPC Limited	1000

Explanation: - For the purposes of this notification, -

- (i) Qualified Institutional Buyers shall have the same meaning as assigned to them in the Securities and Exchange Board of India (Disclosure and Investor Protection) Guidelines, 2000.
- (ii) Retail individual Investors means those individual investors, Hindu Undivided Family (through Karta), and Non Resident Indians (NRIs), on repatriation as well as non repatriation basis, applying for upto rupees ten lakhs in each issue and individual investors investing more than rupees ten lakhs shall be classified as High Net Worth Individuals.
- (iii) The bonds issued to NRIs shall be subject to the provisions of notification number FEMA 4/2000-RB, dated the 3rd May, 2000 and notification number FEMA 20/2000-RB dated the 3rd May, 2000, issued under clause (b) of sub-section (3) of sections 6 and 47 of the Foreign Exchange Management Act, 1999 (42 of 1999), as amended from time to time.
- (iv) The credit rating referred to in paragraph 4 of this notification shall mean the credit rating, as assigned by a credit rating agency which is approved by the Securities and Exchange Board of India as well as the Reserve Bank of India and where an entity has been rated differently by more than one rating agency, the lower of the two ratings shall be considered.

[F.No.178/ 27/2015-ITA-I]

DEEPSHIKHA SHARMA, Director